पालकर, उनको ऊन बचकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रह हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय अंगोरा किस्म की ऊन की कीमत 750 रुपये से 800 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है और इस वष बजट में वस्त्रों पर उत्पादकर लगा देने से अंगोरा ऊन के बाजार को एक गहरा धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अंगोरा ऊन के लघु उद्योग को चौपट होने से चाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि अंगोरा ऊन की कीमत 750/– रुपए से लेकर 800/– रु. प्रति कि. ग्रा. तक होती है । इस वष के बजट में वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप अंगोरा ऊन के बाजार को कोई गहरा धक्का नहीं पहुंचा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Oil seed production

7143. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have proposed any scheme in regard to oilseed production;

(b) if so, whether any arrangements are being considered to provide seeds to farmers on concessional and timely basis;

(c) whether there is also a provision made in the above scheme for exchange of seeds between different states;

(d) if so, whether this scheme has been introduced in Madhya Pradesh; and

(e) what are the concrete proposals formulated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SRH S. KRISHNA KUMAR): (a) to (e) A Centrally Sponsored Oil Seed Production Programme is in operation in 21 States including Madhya Pradesh to increase the production and productivity of oilseed crops. This scheme has a component on assistance for seed production and distribution. There is no component of seed exchange under the Oil Seed Produnotion Programme.

पौध-संरक्षण हेतु सहायता

7144. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौध-संरक्षण यंत्रों, कीटनाशी, कृमिनाशक तथा खरपतवार नाशक औषधियों पर दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को इस वित्तीय वर्ष से बंद कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के सचिवों तथा अन्य प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय संगोष्ठी में उक्त केन्द्रीय सहायता को जारी रखने का अनुरोध किया गया था ;

(ग) क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान होगा; यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या-क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार किसानों के हित में चल रही इस प्रकार की योजनाओं को पुनः आरम्भ करने पर विचार करेगी ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उपकरणों और कीटनाशियों पर केन्द्रीय सहायता की मंजूरी को सकसंगत ठहरा दिया गया है। पौध रक्षण उपकरणों तथा रसायनों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता बहुत सी केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं।

ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) कृषि अनुसंधान वैज्ञानिकों ने, कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सी गैर-रासायनिक व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां शुरू की हैं। कीट प्रबन्ध के नए प्रस्ताव, अर्थात् समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) से गैर-रासायनिक नियंत्रण उपायों के उपयोग को वरियता देने का प्रोत्साहन मिलता है। सरकार ने, राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के खेतों में कृषि विस्तार अधिकारियों तथा किसानों का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शामिल है। 1994–95 के दौरान, समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता, बहुत सी केन्द्रीय केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं।

Lack of funds for projects in farm research

7145. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "No funds for farm research projects" as reported is the Statesman dated 15th April, 1994;

(b) if so, whether the farm research projects in the country are lagging behind;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the allocations made for 1994-95 for farm research projects; and

(e) the details of the scheme formulated for extensive growth of farm research during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The news item refers to reduction of financial support for the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, one of the 18 institutions of the Consultative Group on International Agricultural Research, promoted by the World Bank, Food and Agriculture Organisation and United Nations Development Programme. The news-item does not pertain to reduction of funds for Farm Research Projects of the Indian Council of Agricultural Research funded by the Government of India.

(d) As far as allocations for ICAR are concerned, the budget approved for 1994-95 is as under:

Plan . . .	Rs. 275.00 crores
Non-Plan . .	Rs. 202.00 crores

(e) During the VIIIth Plan period two new National Institutes, 7 National Research Centres and 5 All-India Coordinated Research Projects have been initiated thereby increasing the research activities through a network of 45 Institutes, 4 National Bureaux, 30 National Research Centres, 9 Project Directorates; and 77 All India Coordinated Research Projects.

Losses in the crop yield due to pests

7146. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken at the Central level so far to ascertain State-wise losses accruing to nearly twenty to thirty per-cent of crop yields due to pests and other diseases particularly in Rajasthan and Orissa;